मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक आज से, आठ अप्रैल को फैसलों की घोषणा की जाएगी

आरबीआई के सामने छह नई चुनौतियां

आकलन

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बैठक के फैसलों की जानकारी आठ अप्रैल को दी जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू और वैश्विक दोनों मोर्चों पर कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बैठक दो महीने के अंतराल पर हो रही है। लेकिन इन दो महीनों में घरेलू और वैश्विक हालात काफी बदल चुके हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई बढ़ रही है। इससे आर्थिक विकास प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका में पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता भी भारतीय कारोबारियों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में इस बार आरबीआई के सामने आर्थिक विकास-महंगाई में संतुलन बनाने को लेकर कई नई और कठिन चुनौतियां होंगी। हालांकि, यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आरबीआई इन चुनौतियों के बीच विकास दर को बढ़ावा देने वाले कौन से उपाय अपनाता है।

पिछले दो महीने में वैश्विक और घरेलू मोर्चों पर हालात काफी बदल गए

1 रूस का प्रस्ताव

पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से निपटने के लिए रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत को कारोबार से जुड़े कई प्रस्ताव दिए हैं। इसमें सस्ता कच्चा तेल और रुपया-रूबल में कारोबार प्रमुख शामिल हैं। ऐसे में आरबीआई रूस के प्रस्तावों को ध्यान में रखकर भविष्य की रणनीति बना सकता है।

2 अमेरिकी दबाव

अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों से रूस से व्यापार नहीं करने को कहा है। अमेरिका ने कहा है कि जो देश रूस से कारोबार करेंगे, उनको प्रतिबंध उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। आरबीआई की बैठक में अमेरिकी दबाव पर भी विचार संभव है।

3 युद्ध से उत्पन्न महंगाई

रूस-यूक्रेन युद्ध से दुनियाभर में आपूर्ति श्रंखला प्रभावित हो गई है। जरूरी सामानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर चल रही हैं। इन सब कारणों से महंगाई बढ़ रही है। भारत में कई कंपनियों ने अपनी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ा दी है, जबकि कई कंपनियां बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में आरबीआई के सामने महंगाई पर काबू पाने की प्रमुख चुनौती होगी।

4 पड़ोस में संकट

पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हैं। दोनों देशों में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। दोनों देशों के साथ भारतीय व्यापारियों के हित जुड़े हैं। ताजा संकट के कारण भारतीय कारोबारियों का पैसा फंसा हुआ है। ऐसे में आरबीआई पर इन देशों के साथ कारोबार करने वाले कारोबारियों को राहत देने का भी दबाव होगा।

5 कंपनियों को राहत देना

युद्ध के कारण ठप आपूर्ति श्रंखला और महंगाई के चलते भारतीय कंपनियों को कच्चा माल जुटाने में परेशानी हो रही है। साथ ही माल ढुलाई के लिए कंपनियों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कंपनियों के मुनाफे में कमी आने की आशंका बन रही है। ऐसे में आरबीआई के सामने भारतीय कंपनियों को कारोबार के लिए पैसा उपलब्ध कराने की भी चुनौती होगी।

6 विकास और रोजगार

कोरोना से उबर रही अर्थव्यवस्था आरबीआई की उम्मीदों के अनुरूप रिकवरी नहीं कर पा रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कारोबारी गतिविधियों में गिरावट आई है। बीते कुछ महीनों से देश में रोजगार भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में आरबीआई पर आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ाने के उपाय करने का भी दबाव होगा।

"2022-23 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को कम किया जा सकता है। एमपीसी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वृद्धि का त्याग नहीं करेगी। -अदिति नायर, मुख्य अर्थशास्त्री इक्रा रेटिंग्स

"रिजर्व बैंक के लिए यथास्थिति को कायम रखना मुश्किल होगा। इससे पुनरुद्धार की प्रक्रिया प्रभावित होगी, लेकिन रिजर्व बैंक के पास दरों में बढ़ोतरी से बचने की गुंजाइश नहीं है। -ध्रुव अग्रवाल, सीईओ, हाउसिंग डॉट कॉम